

(b) Compensation has been paid to 147 cases, the balance of 65 cases are being processed.

(c) Rates for compensation were revised since February, 1982 making the same effective from 22nd January, 1982.

(d) and (e) All pending cases prior to April, 1979 have already be cleared except one case of Shri A. Y. Daniel of Shoal Bay village which is still under correspondence.

ARRANGEMENTS FOR TRANSPORTATION OF IMPORTED EDIBLE OIL AND OILSEEDS TO ORISSA

3754. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are satisfied with the arrangements made for transportation of imported edible oil and oilseeds from other cities to the State of Orissa to help the cyclone affected people in that State ;

(b) whether any complaints have been received that certain agencies entrusted with the transportation of imported edible oil and oil seeds are indulging in black marketing, and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND CIVIL SUPPLIES (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF) : (a) to (c) The Central Government allocate only imported edible oils and not oilseeds to States/Union Territories for the public distribution system. Allocated edible oils are supplied to State Union Territories by the State Trading Corporation. For Orissa, these supplies are arranged through the State Trading Corporation's depot at Cuttack. Thereafter, transportation and distribution of this oil are done by agencies nominated by the State Government. No complaint regarding any difficulty about transportation of imported edible oil or its blackmarketing in Orissa has been received by the Central Government.

तिलहन और तेलों के अनुसंधान और विकास उत्पादन और शोधन के लिए बस्तु बोर्ड बनाने का प्रस्ताव

३७४६. श्री राम लाल राह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन और तेलों के अनुसंधान और विकास उत्पादन और शोधन के लिए बस्तु बोर्ड गठित करने का कोई निर्णय किया है और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में की गई कार्यवाही का पूर्ण व्यंग क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) तथा

(ख) : मरमेकिन विकास तथा तिलहन और वनस्पति तेलों का प्रबंध करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बिहार के पलामू, गया और हजारीबाग जिलों में पीने का पानी उपलब्ध न होना

३७५६. श्री रणजीत सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पलामू, गया और हजारीबाग जिलों के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता ;

(ख) क्या इस जिलों में पीने के पानी की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है ;

(ग) क्या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन जिलों के प्रत्येक गांव में 'डायमंड बोरिंग आपरेशन' किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है और यदि नहीं तो यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोष्म नारायण सिंह)

(क) से (घ)

पेय जल पति राज्य का विषय है और ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मार्ग-निर्देशन दे दिए हैं कि पेय जल समस्या के समाधान हेतु न्यूनतम लागत के समाधानों (जैसे